इसी तरह के टावर खड़े करने के लिये। इस ठेके में केवल सिविल इंजीनियरिंग सम्बन्धी काम और टावर खड़े करने का काम किया जा रहा है। टावर डाक और तार विभाग सप्लाई कर रहा है।

- (घ) यह सूचना रेलों के पास उपलब्ध नहीं है।
- (ङ) कम्पनियों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार मैससं एस० ए० ए० एस० इंजीनियरिंग कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड के निदेशकों के नाम इस प्रकार हैं:—
 - (i) श्री एस॰ राय चौधरी
 - (ii) श्री पी० के० साहा
 - (iii) श्री ए० के० सरकार

बोर मैंसर्स एस० ए० ए० एस० टावर (प्राइवेट) लिमिटेड के निदेशकों के नाम इस प्रकार हैं:—

- (i) श्री बी॰ सी॰ गुहा
- (ii) श्री एस॰ राय चौधरी
- (iii) श्री ए० के० सरकार
- (iv) श्री पी० के० साहा ।

निदेशकों के कार्य-काल का रेलों को पता नहीं है।

मुगलसराय रेलवे लोको शैड के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

3928. थी कम चन्द कछवाय : क्यारेलवे मंत्रीयह बताने की कृपाकरेंगे कि :

- (क) क्या यह सच है कि मुगलसराय लोको झैड के कर्मचारियों ने मई, 1968 में हड़ताल की;
- (ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण थे और वे किंद्रने दिनों तक हड़ताल पर रहे; और
- (ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :

- (क) मुगलसराय लोको श्रीड के कुछ सेकेण्ड फायरमैन और क्लीनरों की गैर-हाजिरी और ऊंचे ग्रेडों में स्थानापन्न काम करने से इन्कार करने के कारण गाड़ियों के सामान्य संचालन में क्कावट पड़ी।
- (ख) आदोलन इसलिए किया गया या ताकि ऊंचे ग्रेडों में पदोन्नति/स्यायीकरण आदि सेवा सम्बन्धी अपनी शिकायतों की ओर वे रेल प्रशासन का ध्यान दिला सकें।

यह बताना संभव नहीं है कि आंदोलन कितनी अवधि तक चला क्योंकि बहुत से कर्मचारियों ने बीमार होने की सूचना दी तथा छुट्टी आदि के लिए अर्जी मेजी।

(ग) जिन मांगों पर नियमों के अन्तर्गत विचार किया जा सकता था, उन पर कार्रवाई की गई है।

दिल्ली और नई दिल्ली स्टेशनों पर गाडियों का देर से आना

3929. श्री हुकम चन्द कछबाय : क्यारेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) 24 घण्टों में दिल्ली और नई दिल्ली स्टेशन पर कितनी यात्री गाड़ियां आती हैं और उक्त अवधि में इन स्टेशनों से कितनी यात्री गाड़ियां छुटती हैं;
- (ख) क्या यह सच है कि 17 जून, 1968 को दिल्ली और नई दिल्ली स्टेशन पर पहुंचने वाली अधिकांश यात्री गाड़ियां देर से आई थीं; और
- (ग) यदि हां, तो कितनी गाड़ियां अपने पहुंच समय के पश्चात् पहुंची थीं और वे कितना-कितना समय देर से आई थीं ।

रेसबे मंत्री (श्री चे॰ मु॰ पुनाचा): (क) प्रत्येक ओर से नई दिल्सी/दिल्सी स्टेशनों पर कमशः 52 और 76 गाड़ियां आती हैं और यहां से छूटती हैं।

(ख) और (ग). नीचे यह बताया गया है कि 17 जून, 1968 की दिल्ली/नई दिल्ली स्टेशनों पर लेट बाने वाली गाड़ियों की संख्या क्या थी और वे कितनी लेट थीं :---

स्टेशन		पर और 15 मिनट तक लेट पहुंचने वाली	और 30 मिनट से कम लेट पहुंचने बाली गाड़ियों	30 मिनट से अधिक और एक घण्टा से कम लेट पहुंचने वार गाड़ियों	ने ट प हुंच ने वाली गाड़ियों
दिल्ली .	76	45	9	11	11
नई दिल्ली	52	35	5	5	7

SUPPORT PRICE OF COTTON

3930. SHRI DEORAO PATIL: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

- (a) whether there has been a sharp rice in the prices of cotton from the month of May, 1968 in comparison to the prices prevailing during the months of March-April, 1968;
- (b) whether even now the prices are well above not only the support price for the current season but also the ceiling prices for the year 1966-67; and
- (c) if so, whether Government have accepted the request of cotton growers for raising the support price of cotton for the next year?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI MOHD. SHAFI QURESHI): Yes, Sir, a rising tendency has (a) noticed in the prices of some varieties of cotton since May, 1968. This tendency is, however, due to the normal seasonal factors.

- (b) Yes Sir.
- (c) The matter is under consideration.

PRICE POLICY FOR KAPAS FOR 1968-69

3931. SHRI DEORAO PATIL: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

- (a) whether Government have considered the recommendations of the Agricultural Prices Commission regarding the price policy for kapas for the year 1968-69;
- (b) whether the Commission has recommended to fix the support prices of Kapas which is being sold in the market by the Kapas growers; and
- (c) if so, the broad features thereof and Government's reaction thereto?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI MOHD. SHAFI QURESHI): (a) and (b). No recommendation regarding price of kapas has been made by the Agricultural Prices Commission.

(c) Does not arise.